



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216428
CG-DL-E-27022020-216428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

(मामला सं. ओ.आई.-02/2020)

विषय : थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “फेनोल” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 6/3/2020-डीजीटीआर.—दीपक फेनोलिक लि., हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. तथा एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. (इसके पश्चात आवेदक के रूप में भी संदर्भित) ने थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका (इसके पश्चात संबद्ध देश के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “फेनोल” (इसके पश्चात “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात “नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “फेनोल” है। इस उत्पाद का विपणन दो रूपों में अर्थात् थोक में और पैक किए हुए रूप में किया जाता है। थोक बिक्री सामान्यतया खुले रूप में की जाती है जबकि पैक की हुई बिक्री बहुत छोटे कंटेनर लोड का हो सकता है और उसे सामान्य तौर पर ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का उपयोग फेनोल फार्मल डीहाइड्रेड रेजिन, लेमिनट्स, प्लाईवुड, पार्टीकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, अल्कली फेनोल, फार्मास्युटीकल, डिफेनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है।

4. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत है। हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश वस्तुएं हैं और कथित पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा निर्मित वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों के मामले में अथवा अंतिम उपयोगों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथमदृष्टया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें इस नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग

6. यह आवेदक मै. दीपक फेनोलिक लि., हिंदुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल लि. तथा एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों का भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत उत्पादन है क्योंकि भारत में आवेदकों को छोड़कर संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदकों ने दावा किया है कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का न तो उन्होंने आयात किया है और न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक अथवा किसी निर्यातक से उनका कोई संबंध है।

7. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के संबंध में “घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से” किया गया है।

कथित पाटन का आधार

थाइलैंड तथा यू एस ए के लिए सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने थाइलैंड और यूएसए में घरेलू कीमतों पर विचार करने के बाद सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस प्रयोजन से, आवेदकों ने थाइलैंड और यू एस ए के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु बाजार अनुसंधान एजेंसी, आई सी आई एस मासिक बुलेटिन द्वारा रिपोर्टों पर विचार किया है। उपयुक्त तुलना के लिए कारखानागत स्तर तक आई सी आईएस रिपोर्टों में उलब्ध सी एफ अगार कीमतों को लाने के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

निर्यात कीमत

9. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के लेनदेन वार आयात आंकड़ों तथा उनके मासिक प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत की गणना की है। विदेशी भाड़े, समुद्री बीमा, पोर्ट संबंधी खर्च, कमीशन और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किए गए हैं। सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना पूर्व-कारखाने स्तर पर की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन को दर्शाता है।

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के मामले में पाटन मार्जिन के दर्शाता है, जो कि विषय देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी हैं, और पर्याप्त हैं। इस बात का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जाता है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने घरेलू उद्योग पर जांच की अवधि और कीमत न्यूनकारी प्रभाव के दौरान पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के परिणामस्वरूप उनके कार्य निष्पादन पर लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान हानि हुई हुई है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक क्षमताओं और घरेलू बिक्री कीमतों पर आयात की कीमतों के न्यूनकारी प्रभाव को देखते हुए घरेलू उद्योग को आगे क्षति होने का खतरा है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है।

शुल्कों को प्रतिगामी प्रभाव से लगाना -

12. आवेदकों ने निम्नलिखित दावा करके पाटनरोधी शुल्क को पश्चगामी प्रभाव से लगाए जाने का अनुरोध किया है :

- क. इस देश में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है। न केवल यू एस ए तथा थाइलैंड से पाटन का इतिहास है बल्कि अनेक अन्य देशों से भी पाटन का इतिहास है।
- ख. भारत में आयातकों को इस बात की जानकारी है कि भारत में फिनोल का पाटन निर्यातकों द्वारा किया जाता है। आयातकों को भी इस बात की जानकारी है कि इस कार्य की कार्य पद्धति से भारतीय उत्पादकों को क्षति होगी।
- ग. निर्यातकों ने व्यापक पाटन का सहारा लिया है और वह इस तथ्य से पूर्ण रूप से स्थापित है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान मासिक आधार पर बहुत अधिक रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान बहुत तेजी से गिरावट हुई है।

13. हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में इस अधिसूचना के पैरा 22 में दी गई समय सीमा के अनुसार टिप्पणियाँ कर सकते हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस प्रकार की कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में और इस नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, यदि उसे लगाया जाए, तब वह घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते हैं।

संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

16. आवेदकों ने 1 जून, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक (6 माह) की जांच की अवधि का प्रस्ताव किया है। हालांकि प्राधिकारी को हाल ही के आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए, वर्तमान जांच में जांच की अवधि (इसके पश्चात "पी ओ आई" के रूप में भी संदर्भित) 1 जुलाई, 2019 से 31 दिसंबर 2019 (6 महीने)

है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2016 से 30 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 30 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 और जांच की अवधि होगी।

प्रक्रिया

17. इस नियमावली के नियम 6 में दिए गए अनुसार सिद्धांतों का पालन वर्तमान जांच के लिए किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में इसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक् रूप से सूचित किया जा रहा है।

19. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकते हैं।

20. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रेषित किए जा सकते हैं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उस अनुरोध का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जिससे कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। हालांकि यह भी नोट किया जाए कि उप नियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है जब इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हो अथवा प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं हो, तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जांच परिणामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समयसीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में जारी किए गए व्यापार नोटिसों के संबंध में उसका एक अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर प्रत्युत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में “गोपनीयता” का दावा किया गया है तो, दो अलग-अलग सैटों में उन्हें दायर करना अपेक्षित है।

- i. एक सैट गोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित), और
- ii. दूसरा सैट अगोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित)।

26. “गोपनीय अथवा अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट से चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट प्रतियां प्रत्येक की चार (4) सैटों में हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

27. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति के हैं और/अथवा अन्य प्रकार की सूचना है जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा गोपनीय के रूप में दावा किया गया है। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानतः अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।

29. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाली इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

30. उसके सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

31. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस.भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2020

(Case No. O.I.-02/2020)**Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Phenol” originating in or exported from Thailand and United States of America.**

F. No. 6/3/2020-DGTR.—Deepak Phenolics Ltd., Hindustan Organics Chemicals Ltd. and SI Group India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the “Applicants”) have filed a joint application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Anti-dumping investigation on imports of “Phenol” (hereinafter also referred as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from Thailand and United States of America (also referred to as “subject countries”).

2. The Applicants have alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry, and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Phenol”. The product is marketed in two forms i.e. bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed sales can be of much smaller container loads and are generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.

4. This product is classified under Customs Tariff heading No. 2907.11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

5. The Applicants have claimed that the PUC, which is dumped into India, are like article to the goods produced by the domestic industry and that there are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the alleged dumped imports and the domestically produced goods manufactured by the Applicants. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules.

Domestic industry

6. The Application has been jointly filed by Deepak Phenolics Ltd., Hindustan Organics Chemicals Ltd. and SI Group India Pvt. Ltd. Applicants account for 100% of Indian production as there is no other producer of the subject goods in India, apart from the Applicants. The Applicants have claimed that neither they have imported the PUC from the subject countries in the period of investigation nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.

7. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis for Alleged Dumping**Normal value for Thailand and USA**

8. The Applicant has claimed normal value by considering the domestic prices in Thailand and USA. For this purpose, the Applicants have relied upon reports by market research agency, ICIS monthly bulletin for determination of normal value for Thailand and USA. Appropriate adjustments have been made to bring the CFR prices available in ICIS Reports to ex-factory level for appropriate comparison.

Export price

9. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction wise import data as well as their monthly

published data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission and inland freight.

10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin, which is above the *de-minimis*, and is significant in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

11. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of dumped imports during the Period of Investigation and price depressing effect on domestic industry. The Applicants have claimed that as a result of dumped imports of subject goods from subject countries, their performance have been adversely impacted in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The Applicants have further claimed that they have suffered losses during the Period of Investigation on account of dumped imports of subject goods from subject countries. The Applicants have also claimed that there is a further threat of injury to the domestic industry in view of significant capacities of subject goods in subject countries and depressing effect of import prices on domestic selling prices. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

Retrospective imposition of duties

12. The Applicants have requested for retrospective imposition of the antidumping duty by claiming the following:

- a. There is clear history of dumping of the product in the country. Not only there is history of dumping from USA and Thailand, but also from a number of other countries.
- b. The importers in India are aware of the fact that exporters practice dumping of Phenol into India. The importers are also aware that such a practice would cause injury to the Indian producers.
- c. The exporters have resorted to massive dumping is well established by the fact that the dumping margin has remained significant on monthly basis during the period of investigation.
- d. The performance of domestic industry has steeply declined over the period of investigation.

13. The interested parties may offer their comments this regard as per time limit given in para 22 of this notification.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

14. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

15. The subject countries for the present investigation are Thailand and United States of America.

Period of Investigation (POI)

16. The Applicants have proposed period of investigation from 1st June 2019 to 30th November 2019 (6 months). However, for enabling the Authority to make required analysis based on more recent data, the Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") in the present investigation is 1st July 2019 to 31st December 2019 (6 months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016- 30th March 2017, 1st April 2017- 30th March 2018, 1st April 2018- 30th June 2019 and the POI.

Procedure

17. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

18. The exporters in the subject countries, their government through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
20. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi – 110001

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties

Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority